(b) The North Eastern region has seasonal surplus during monsoon months mainly during off-peak hours. During the remaining period North-Eastern region has been drawing power from Eastern region.

(c) and (d) North-Eastern region is connected with Eastern region through 220 KV Bongaigaon-Birpara line and major part of North-Eastern region is operating in parallel with Eastern region. The Eastern region is quite surplus in power and has been exporting power to the neighbouring Southern, Eastern and Western regions. The existing transmission system between Eastern region and other regions is being utilised to export Eastern region surplus and there is no possibility of exporting surplus of North-Eastern region to other regions in the near future.

Losses Suffered by NTPC

3144. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether NTPC has incurred losses of Rs. 220 crores during the last one year due to malfunctioning boiler tubes in its power plants as reported in the Hindustan Times dated 29th June, 1998;

(b) if so, whether accountability for losses suffered by NTPC have been fixed;

(c) if so, the details thereof;

(d) the details of total losses suffered by each of the power plant run by NTPC during the last three years, year-wise and plant-wise; and

(e) the steps taken by Government to check losses?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM): (a) No, Sir. The news report in the Hindustan Times dated 29th June, 1998 was reported out of context.

(b) and (c) Do not arise.

(d) Boiler tube failure in power plants in an accepted phenomenon the world over. The percentage loss of availability due to tube failure in NTPC stations is comparable to international utilities of USA and UK, and has come down to 1.89% in 1997-98 from 2.064% in 1996-97, which is considered as one of the best performances in the country. The tube failure rate expressed in terms of number of tube failures per thousand running hours of NTPC stations for the last three years is as under:—

Year	Tube failure rate per thousand running hours
1995-96	0.351
1996-97	0.338
1997-98	0.294

(e) Continuous monitoring of boiler tube failure is undertaken in NTPC stations so as to explore the strategies to reduce the failure to the minimum possible level. The International Conference on Tube Failure organised by NTPC recently was intended to provide a platform for sharing national and international experiences with the object of exploring strategies to reduce tube failure.

टिहरी बांध पर हुआ व्यय

3145. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि टिहरी बांध पर अब तक हुए व्यय का बड़ा भाग अनुत्पादक कार्यों पर व्यय हुआ है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भवन, निर्माण, जिलों नया टिहरी नगर एवं अधिलेट की कालोनी भी शामिल है, पर कितनी राशि व्यय हुई है;

(ग) मुख्य बांध टनल एवं पावर हाऊस पर कितनी राशि व्यय हुई है; और

(घ) अन्य वार्षिक स्थापना व्यय क्या हैं?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) जी, नहीं। टिहरी जल विद्युत परियोजना पर किया गया व्यय अनुमोदित लागत अनुमानों के अनुसार अध्ययनों और परीक्षणों, अनिवार्य अवसंरचनात्मक कार्य,

4169/RS/F-4-B

परियोजना प्रभावित जनता का पुनर्वास और पर्यावरण संबंधी कार्यों सहित अनिवार्य परियोजना कार्यों से संबंधित है।

(ख) पुनर्वास कार्यों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान नये टिहरी टाऊन और पुनर्वास कॉलोनी सहित 64.92 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

(ग) 1997-98 तक मुख्य बांध सुरंगों और विद्युत कार्यों पर 600.54 करोड़ रुपये के राशि का व्यय किया गया।

(घ) परियोजना पर विद्यामान वार्षिक स्थापना व्यय 18.06 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है जो कि 1997-98 में किए गए व्यय पर आधारित है।

Clearing of Power Projects

3146. DR. MAHESH CHANDRA SHARMA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether the Central Government are considering to raise the limit of Rs. 1.000 crores for sanctioning the projects by the State Governments without referring it to be Central Government (Central Electricity Authority) for techno-economic clearances; and

(b) when the private sector power projects are considered based on competitive bidding for price than what will be the procedure of Central Electricity Authority in clearing such power projects?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM): (a) Power projects of private generating companies costing up to Rs. 100 crores (in case of projects awarded through Memorandum of Understanding/Letter of Intent, etc. route) and costing up to Rs. 1.000 crores (in case of projects awarded through competitive bidding) do not have to obtain techno-economic clearance of the Central Electricity Authority and can be cleared by the concerned State Government/State Electricity Board.

(b) The Central Electricity Authority, while considering accord of techno-economic clearance to competitively bid projects, is guided by the relevant sections of the Electricity (Supply) Act, 1948 and the procedure prescribed by the State Electricity Boards in their bidding documents. Government of India has brought out a Notification for award of thermal power projects through competitive bidding in May 1997.

उड़ीसा में विद्युत क्षेत्र में सुधार

3147. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिजली क्षेत्र में सुधार अभियान के तहत् उड़ीसा में 1992 से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस सुधार अभियान के तहत निजी क्षेत्र को बिजली के उत्पादन और ट्रांसमिशन आदि क्षेत्र में शामिल किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि आज उड़ीसा में बिजली उत्पादन राज्य में बिजली की खपत से अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर उड़ीसा में बिजली क्षेत्र में अपनायी गयी नीति से भिन्न जिला नीति बनाने पर विचार किए जाने के क्या कारण है?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा सरकार निजी क्षेत्र को विद्युत के उत्पादन और वितरण के लिए विद्युत संयंत्रों की स्थापना किए जाने हेतु प्रोत्साहित करती रही है। पारेषण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र शामिल नहीं है।

(ग) उड़ीसा में विद्युत का उत्पादन इसकी खपत से कम है, हालांकि केन्द्रीय स्टेशनों में उड़ीसा के हिस्से सहित विद्युत की उपलब्धता राज्य में खपत से कहीं अधिक है।

(घ) केन्द्र सरकार ने टैरिफों के यौक्तिकरण तथा उससे संबंधित मामलों के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा राज्यों में राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना के लिए विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 लागू किया है। यह अधिनियम राज्य विद्युत क्षेत्र की पुनर्संरचना के लिए